of India have also taken steps to rationalise the internal distribution of available pesticides within the country. To minimise the use of pesticides, the Government of India have taken steps to establish pest surveillance forecasting and warning systems so that pest epidemics could be controlled before it assumes large proportions. The Government of India is also paying increasing attention to the biological control of pests, and thereby minimise the use of psticides.

श्री अनादि चरण दास : अध्यक्ष महोदय, इस के अन्दर जितनी पैस्टीसाइड की जरूरत है उस का उत्पादन देश में करने में क्या कठिनाइयां हैं? अपनी अवश्यकता के मुताबिक पेस्टीसाड का उत्पादन क्यों नहीं होता है?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: Many of the pesticides are petro-chemical based and because of the energy crisis, some of the basic raw materials are scarce all over the world. But as far as the general programme of production is concerned, we are very much ahead. We are producing within the country large part of our requirements. Our future aproach is also to see that to the extent possible we succeed in organising production programme in our country itself. But there are certain basic raw materials which are not available. That has been the difficulty, not the technical knowhow. In fact, we have enough technical knowhow.

श्री अनादि चरण दास : जो कैमिकल्ज आप मंगाते हैं बाहर से वे कौनसी हैं और किन देशों से मंगाई जाती हैं?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: The chemicals are many. For instance BHC and DDT mainly we manufacture in the country and only a small portion is imported from USSR, USA, Poland and a number of other countries. Endrine, Carbaryl and Endosulfar we import from USA. There are a few other chemicals which are imported from Western Europe.

SHRI G. VISWANATHAN: What is the total requirement of pesticides in the country and what is our production? What is the total value of the imports? When are we going to become self-sufficient in pesticides?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: There are different plant protection materials. BHC is a very important chemical where our requirement is 30,000 and we produce 24,000 tonnes. So, the shortfall is 6,000 tonnes. In the case of DDT our requirement is 7,500 tonnes and we produce 4,000 tonnes. Endrine is an item we import. In the case of carbaryl we import 5,000 tonnes and Endosulfar about 800 to 1,000 tonnes. Roughly, our broad requirement is 56,000 and we manufacture about 35,000 tones.

SHRI BISWANARAYAN SHASTRI: Just now the hon. Minister said the shortage of pesticides and raw materials is mainly petro-based. May I know whether any effort will be made to find out an alternative raw material for production of pesticides

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: It is a very difficult proposition. If such a raw material or feed stock is easily available, we would be very happy. Some research effort is going on but it is not that easy.

Committee on Development of Urdu

*85. SHRI S. N. MISRA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Gujarat Committee on Development of Urdu in the country has since submitted its report to the Government;

(b) if so, the findings of the Committee; and

(c) Government's reaction in regard thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV): (a) The Committee for Promotion of Urdu (Gujral Committee) has not yet submitted its report to Government.

(b) and (c) Do not arise.

SHRI S. N. MISHRA: When is it expected that the report would be submitted?

SHRI D. P. YADAV: Very soon.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या सरकार ने कोई आधार निश्चित किया है जिसको ध्यान में रखकर किसी प्रदेश की राज भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा को वहां की राज भाषा का दर्जा दिया जा सकता है ?

श्री डी० पी० यादव . प्रश्न नही उठता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अगर मन्त्री महोदय उठते है तो सवाल क्यो नही उठ सकता है ? इसको बदल कर मै पेश करना चाहता हू। क्या यह सच है कि उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा बनाने की माग की जा रही है यदि हा तो दूसरी राजभाषा बनाने के बारे में क्या सरकार ने कोई कसौटी निर्धारित की है जिस पर कस कर किसी भाषा को किसी प्रदेश की दूसरी राज भाषा का दर्जा दिया जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह गुजराल समिति के बारे मे सवाल है पता नही उस मे क्या उठेगा। आपने पहले ही उठा दिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह सवाल उठता रहा है। आप याद रखिये कि चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश मे यह बात कही जाती रही है कि सरकार उर्दू का विकास चाहती है। मामला गजराल समिति को सौपा गया है।

अध्यक्ष महोदय : रिपोर्ट तो आने दीजिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अच्छा यह बता दिया जाए कि क्या उर्दू को दूसरी राज भाषा का दर्जा देने का सवाल भी गुजराल समिति के जेरे गौर है ?

श्री डी० पी० यादव : अच्छा होता, यह प्रश्न गृह मन्त्रालय से पूछा गया होता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने सुना इनका जवाब ? अच्छा इतना बता दिया जाय कि उर्दू को किसी दूसरे प्रदेश में दूसरा दर्जा दिया जाय, क्या समिति इस पर विचार कर रही है ?

श्री डी० पी० यादव . गुजराल कमेटी की जो टर्म्स आफ रेफ्रंस है उनको मै पढ़ देता हूं।

अध्यक्ष महोदय है या नही है। इतना ही बता दीजिये।

श्री डी० पी० यादव जरा ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। थोडा सा है

"To advise the Government on the measures to be adopted for the promotion of the Urdu language and the steps required to be taken to provide adequate facilities for Urdu-speaking people in educational, cultural and administrative matters"

श्री शंकर दयाल सिंह इस समिति का गठन कब हुआ था, इसने अब तक किन-किन राज्यों का दौरा किया है और इस समिति के कौन-कौन सदस्य है ?

श्री डी० पी० यादव . यह कमेटी मई 1972 मे बनी थी। इसके सोलह सदस्य थे। अगर आप कहे तो मै सबके नाम पढ़ दू लेकिन इस कमेटी ने ग्यारह राज्यों का दौरा किया है।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा : जिन स्टेट्स मे उर्दू ज्यादा बोली जाती है वहा इसको दूसरी राजभाषा बनाने मे क्या दिक्कत है ? क्या यह सच है कि आन्ध्र मे उर्दू को दूसरी राज भाषा बनाया गया है ? यदि हा, तो उत्तर प्रदेश मे इसको दूसरी राज भाषा बनाने मे क्या दिक्कत है।

अध्यक्ष महोदय रिपोर्ट नहीं आई है। आप इधर उधर घूम रही है।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा : दूसरी बात राज भाषा बनाने से इसका डिवलपमेंट ज्यादा होगा। क्या इसको भी आप ध्यान मे रखगे ?

श्री एस० एम० बनर्जी : दो साल बीत जाने के बावजूद भी रिपोर्ट नही आई है। मेरा ख्याल है कि जब तक रिपोर्ट आएगी शायद उर्दू जबान दम तोड देगी। म जानना चाहता हू कि इस कमेटी की स्थापना के अलावा भी क्या सरकार आज उर्दू जबान की तरक्की के लिए कोई कदम उठा रही है ? मैं आप से हाथ जोड कर निवेदन करना चाहता हू कि आप पार्लियामेंट म इस तरह की व्यवस्था करदे कि अगर कोई उर्दू जबान मे बोलेगा तो वह उर्दू मे ही लिखी जायेगी। इसका भी आज कोई इतजाम नही है। शमीम साहब उर्दू मे बोलते है। मै भी उर्दू म उल्टे सीधे बोलने की कोशिश करता हू। लेकिन म निवेदन करूगा कि उस रिपोर्ट से पहले कम से कम यह जो आप के हाथ मे है यह तो कर दीजिए ताकि उर्दू बोलने वालो को यकीन हो जाय कि आप के रहते हुए आप के नीचे उर्दू जबान कभी मरेगी नही पार्लियामेंट की जुबानो मे उर्दू भी एक जबान रहेगी।

अध्यक्ष महोदय आप मे यह इस तरह मुखातिब कर रहे है जिस से कि आप भी इस का जवाब इन के दलायल पर दे दे।

मैं भी उर्दू बोलने लग गया हू।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा मतलब है कि उर्दू में लिखी जाय। पहले लिखी जाती थी उर्दू जबान मे। (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय : अभी जब वह रिपोर्ट आ जायेगी तो वह इस हाउस के सामने पेश होगी। अभी से आप पहले ही इस पर क्यो इतने फिक्रमद हो रहे है। अभी जो चीज इस के दायरे मे आती नही है कैसे वह इस का जवाब दे दे जब तक रिपोर्ट सामने नही आए।

श्री मधु लिमये : मैं मत्री महोदय से जानना चाहता हू कि क्या उन को इस बात का पता है कि उर्दू इस देश की मिट्टी की जबान है यह पाकिस्तान या और किसी राज्य की जबान नही है ? तो काम से कम काश्मीर की तरह दो तीन राज्यो मे इस को और ज्यादा सहूलियत और मौके देने के बारे मे मन्त्री महोदय सोचेगे ?

अध्यक्ष महोदय : लिमये जी यह तो गुजराल कमेटी के बारे मे सवाल है। बाहर से यह चीज कैसे आ गई इस मे ?

श्री मधु लिमये : गुजराल कमेटी क्या कर रही हे दो साल से ? (व्यवधान) पहले यह तो साफ हो जाय कि क्या मन्त्री महोदय उर्दू को इस मिट्टी की जबान मानते हे क्योकि बहुत सारे लोगो को यह गलतफहमी होगी, कि यह पकिस्तान की जबान है ?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे अध्यक्ष महोदय उर्दू हमारी पन जबान है। हमारे मध्य प्रदेश के लोग भी उर्दू से मुहब्बत करते है उसकी तरक्की मे हमारी रुचि है हम चाहते है कि इस जबान की तरक्की हो। इसलिए हम चाहते है कि यह जबान आम लोगो तक पहुचे मगर जैसे इल्लिटरेट लोगो तक पहुचे इस के लिए क्या इस कमेटी की रिपोर्ट कम से कम देवनागरी लिपि मे लिख कर देगे ताकि हम लोग पढ़ कर समझ ले कि इस की तरक्की के लिए क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : सवाल तो गुजरात कमेटी से चलता है कुछ उस से चल कर राज भाषा में चले गए और फिर दूसरे मिट्टी में आ गए कि उर्दू हमारी मिट्टी की जबान है और आप तरीकाए मोहब्बत बताने लगें।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : देवनागरीलिपि में रिपोर्ट तो आए ताकि हमारे जैसे इल्लिटरेट लोग उसे पढ़ सकें।

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN): The report of the Committee will be placed on the Table of the House. ....

SHRI S. A. SHAMIM: When? It was constituted in 1972.

PROF. S NURUL HASAN. When the Committee submits its report and after it has been considered by the Government, the report will be placed on the Table of the House in accordance with the normal procedure

World Bank Development Project for Drought-Prone Areas

*86. SHRI DHAMANKAR:
SHRI P. M. MEHTA:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Gujarat State have protested to the Central Government for not giving fair treatment while selecting six districts for the Rs. 82 crore World Bank Development Project for the drough-prone areas;

(b) the main reasons for not including Gujarat Districts under the said scheme; and

(c) whether the project will give much benefit to the States of Maharashtra and Rajasthan whereas Gujarat, though worst affected by continuous drought, has been left out?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SHAH NAWAZ KHAN): (a) No, Sir.

(b) The World Bank wanted to take up a small programme as a pilot project. In view of the equally deserving claims of several districts in several states, it is inevitable that some states should get excluded from the World Bank Assistance.

(c) Under the World Bank aided projects, the six districts selected in the four states of Karnataka, Rajasthan, Maharashtra and Andhra Pradesh will get additional financial assistance from the Centre to be matched equally by the state governments.

SHRI DHAMANKAR: In view of the recent Rome Conference deliberations, it is more likely that more aid from international agencies will be forthcoming for chronically drought-affected areas including those in India and it is natural that each State feel that they should get advantage of these schemes. From the statement of the Minister, it seems that only six districts have been selected and in Maharashtra, the two districts of Sholapur and Ahmednagar whose soil and crop conditions are the same have been selected instead of districts with different crop conditions and soil conditions like Konkan and Marathwada. In view of this I would like to know whether the State Governments were consulted before proposing the districts for World Bank assistance and any committee of experts were appointed to ensure that the selection of districts was based on certain objective criteria and definite guidelines to avoid bickering among the States?

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: As the hon. Member knows, we have already under implementation about 72 drought-prone area projects. This offer by the World Bank was only for a limited number. Initially we proposed 16 districts. Then they sent a team and the team said that they would like to take up 6 projects in four districts. We are expecting that some more districts under the World Bank programme will be taken up. If that happens, we